

[2023] 10 एस सी आर 913:2023 आई. एन. एस. सी 651

/

रहीम शाह और ए. एन. आर.

सरकार सिंह और हमारा।

(2023 की सिविल अपील संख्या 4628) 24 जुलाई, 2023

/

[ए. एस. बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर मुकदमे में विलंब-दोषसिद्धि-निचली विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था-अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 दायर याचिका में, निचली अपील विचारण न्यायालय द्वारा सीमा के आधार पर खारिज कर दिया गया था-अपीलकर्ताओं द्वारा दायर दूसरी अपील को भी उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-आयोजित:चूंकि निचली अपीलीय अदालत के समक्ष अपील में तर्क यह था कि निर्णय अपीलार्थियों की जानकारी में नहीं था, इसलिए मामले के उस पहलू को निचली अपीलीय अदालत द्वारा ध्यान में रखने की आवश्यकता थी क्योंकि वास्तव में अपीलार्थियों ने लिखित बयान दायर करने के अलावा प्रभावी भाग नहीं लिया था-जब अपील दायर करने में केवल 52 दिनों की देरी हुई थी और इसके अलावा जब पक्षकार अचल संपत्तियों पर अधिकार के संबंध में मुकदमा कर रहे थे, तो पक्षों के बीच पर्याप्त अधिकारों का फैसला किया जाना था-जिस तरह से निचली अपीलीय अदालत ने देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया था जब देरी अत्यधिक नहीं थी-उच्च न्यायालय ने भी केवल इस आधार पर अपील को खारिज करने में उचित नहीं ठहराया कि विधि का कोई प्रश्न ही नहीं था। धारा 96-सीमा अधिनियम, 1963 -एस 5-अभ्यास और प्रक्रिया।

/

/

/

/

कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्न बनाम एमएस.

काटीजी और ओआरएस। (1987) 2 एससीसी 107:[1987] 2 एस. सी. आर. 387-निर्भर।

/

संदर्भित निर्णय

[1987] 2 एससीआर 387

पर विश्वास किया

पैरा 4

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2023 की सिविल अपील सं. 4628।

/

913 ए.

914

/

[2023] 10 एस सी आर।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 16.04.2015 के निर्णय और आदेश से, 2010 के एस. ए. संख्या 1185 में जबलपुर में प्रधान सीट। विकास उपाध्याय, नितिन गौर, कौस्तुभ अंशुराज, कुबेर बोध, अर्जुन सिंह तोमर, सुश्री अंकिता कश्यप, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। अभिषेक विकास, अंशुमन श्रीवास्तव, अभिजीत श्रीवास्तव, अभिषेक शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

/

निर्णय

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय दिया गया: अनुमति दी गई।

/

1. पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना और अपील पत्रों का अध्ययन किया।
2. यहाँ प्रतिवादी संख्या 1 सिविल वाद संख्या 3 ए/02 वाले मूल वाद में वादी है। मुकदमे का फैसला निचली विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 01.10.2005 के निर्णय के माध्यम से किया था। अपीलार्थी, जो मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 1 और 2 थे, ने उक्त निर्णय को लागू करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत एक नियमित प्रथम अपील दायर की। चूंकि अपील दायर करने में 52 दिनों की देरी हुई थी, इसलिए सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। निचली अपीलीय न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से सिविल अपील 2 वाली अपील को इस सीमा के आधार पर खारिज कर दिया था कि देरी को ठीक से समझाया नहीं गया है और इसके

परिणामस्वरूप अपील को खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय के खिलाफ, अपीलकर्ता मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष No.1185/2010 वाली दूसरी अपील में थे। दूसरी अपील को उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 1 के निर्णय के माध्यम से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि विचार के लिए विधि का कोई प्रश्न ही नहीं है।

/

/

/

3. यह उस प्रकाश में है, अपीलार्थी इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष हैं। शुरुआत में, इस बात पर ध्यान देने के बाद कि निचली अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील में तर्क यह था कि निर्णय अपीलार्थियों की जानकारी में नहीं था, मामले के उस पहलू को निचली अपीलीय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना आवश्यक था क्योंकि अपीलार्थियों ने वास्तव में लिखित बयान दाखिल करने के अलावा प्रभावी भाग नहीं लिया था। जब अपील दायर करने में केवल 52 दिनों की देरी हुई और इसके अलावा जब पक्षकार अचल संपत्तियों पर अधिकार के संबंध में मुकदमा कर रहे थे, तो पक्षकारों के बीच पर्याप्त अधिकारों का निर्णय लिया जाना था। देरी को माफ किया जा सकता था और अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता था।

/

/

915

रहीम शाह और ए. एन. आर. सरकार सिंह और हमारा।

/

4. कलेक्टर, भूमि अधिग्रहण, अनंतनाग और अन्न के मामले में यह न्यायालय । बनाम। एमएस. (1987) 2 एस. सी. सी. 107 में रिपोर्ट किए गए काटीजी एंड ओ. आर. एस. ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

“विधायिका ने 1963 के भारतीय सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करके देरी को माफ करने की शक्ति प्रदान की है ताकि अदालतें 'गुण-दोष' के आधार पर मामलों का निपटारा करके पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय कर सकें। विधायिका द्वारा प्रयुक्त 'पर्याप्त कारण' अभिव्यक्ति अदालतों को विधि को सार्थक तरीके से लागू करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त रूप से लोचदार है जो न्याय के उद्देश्यों को कम करता है-जो अदालतों की संस्था के अस्तित्व के लिए जीवन-उद्देश्य है। यह सर्वविदित है कि यह न्यायालय इस न्यायालय में स्थापित मामलों में न्यायोचित रूप से उदार दृष्टिकोण अपना रहा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह संदेश पदानुक्रम के अन्य सभी

न्यायालयों तक नहीं पहुंचा है। और इस तरह का एक उदार दृष्टिकोण सिद्धांत रूप में अपनाया जाता है क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि:

/

/

1. आम तौर पर एक वादी को देर से अपील दायर करने से लाभ नहीं होता है।

/

2. देरी को माफ करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप एक सराहनीय मामले को बहुत हद तक बाहर फेंक दिया जा सकता है और न्याय का कारण विफल हो सकता है। इसके विपरीत जब देरी को माफ कर दिया जाता है तो सबसे अधिक जो हो सकता है वह यह है कि पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर एक कारण तय किया जाएगा।

/

3. "हर दिन की देरी को समझाया जाना चाहिए" इसका मतलब यह नहीं है कि एक पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। हर घंटे की देरी, हर सेकंड की देरी क्यों नहीं? इस सिद्धांत को तर्कसंगत सामान्य ज्ञान व्यावहारिक तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

/

4. जब एक दूसरे के खिलाफ पर्याप्त न्याय और तकनीकी विचार रखे जाते हैं, तो पर्याप्त न्याय के कारण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि दूसरा पक्ष गैर-जानबूझकर देरी के कारण किए जा रहे अन्याय में निहित अधिकार होने का दावा नहीं कर सकता है। 5. ऐसा कोई अनुमान नहीं है कि देरी जानबूझकर, या दोषपूर्ण लापरवाही के कारण, या दुर्भावना के कारण की गई है। एक वादी को देरी का सहारा लेने से लाभ नहीं होता है। वास्तव में वह एक गंभीर जोखिम उठाता है।

/

6. यह समझना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान तकनीकी आधार पर अन्याय को वैध बनाने की अपनी शक्ति के कारण नहीं किया जाता है, बल्कि

/

916

/

[2023] 10 एस सी आर।

/

क्योंकि यह अन्याय को दूर करने में सक्षम है और ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है।

इस दृष्टिकोण से न्याय-उन्मुख दृष्टिकोण बनाते हुए, अपील की स्थापना में देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण था। "

/

5. सभी अदालतों में न्याय उन्मुख दृष्टिकोण के इरादे को व्यक्त करने वाला उपरोक्त निर्णय लगभग तीन दशक पहले प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से यह मामला व्यापक असंवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसने संबंधित वादियों की पीड़ा को जारी रखने के अलावा न्यायिक पदानुक्रम पर भी अनावश्यक रूप से बोझ डाला है, जिसे पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद घड़ी को इस दूर के बिंदु पर वापस सेट करना होगा और अपनी पीड़ा को लंबा करना होगा। यदि केवल संबंधित न्यायालय कठोर तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय न्याय उन्मुख दृष्टिकोण के प्रति संवेदनशील होता, तो पक्षों के बीच मुकदमेबाजी शायद उनके प्रतिद्वंद्वी विवाद के गुण-दोष पर निर्णय के बाद बहुत पहले समाप्त हो जाती।

/

/

6. यदि यह स्थिति है, तो जिस तरह से निचली अपीलीय अदालत ने देरी के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है, जब देरी अत्यधिक नहीं थी, वह उचित नहीं है और उच्च न्यायालय भी केवल इस आधार पर अपील को खारिज करने में उचित नहीं था कि विधि का कोई प्रश्न ही नहीं था।

/

7. इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 16.04.2015 के निर्णय के साथ-साथ निचली अपीलीय अदालत द्वारा पारित दिनांक 08.10.2010 के निर्णय को भी दरकिनार कर दिया जाता है। निचली अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने में देरी को माफ कर दिया जाता है। दीवानी अपील संख्या 35 ए/2005 को निचली अपीलीय न्यायालय यानी प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नसरुल्लागंज, जिला सीहोर, एम. पी. की फाइल में बहाल कर दिया गया है। पक्षकार गुण-दोष के आधार पर अपनी दलीलें रखेंगे। सभी विवाद खुले रहते हैं।

/

8. पक्षकार उपस्थिति के लिए पहली तारीख के रूप में 23.08.2023 पर 11.00 AM पर नए नोटिस/समन जारी किए बिना निचली अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश होंगे। इसके बाद निचला अपीलीय न्यायालय अपनी कार्यवाही को विनियमित कर सकता है और अपने गुण-दोष के आधार पर और विधि के अनुसार मामले का जल्द से जल्द निपटारा कर सकता है।

/

9. तदनुसार, अपील का निपटारा किया जाता है।

10. लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

/

दिव्या पांडे

अपील का निपटारा किया गया।